

[2023] 2 एस. सी. आर 756

आय कर अधिकारी

बी.

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया

(2022 की सिविल अपील संख्या 911)

अप्रैल 06,2023

[एम. आर. शाह और बी. बी. नागरत्ना, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961: s.153C-किसी अन्य व्यक्ति की आय का आकलन-यू/एस द्वारा खोज की शुरुआत। 132 संशोधन से पहले

से एस। 153 सी-संशोधित एस की प्रयोज्यता। 153 सी-तथ्यों पर, यू/सर्च करें s.132 परिसर में 04.09.2013 और s पर आयोजित किया जाता है। 153 सी जैसा कि यह तब था लागू था-डब्ल्यू. ई. एफ। 01.06.2015, s.153C वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित-धाराओं के संशोधन के बाद 25.04.2017 पर तलाशी के अलावा व्यक्ति की लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या संपत्ति को आकलन अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया। 153 सी-नोटिस जारी करना यू / 04.05.2018 पर s.153C-आयोजित: एस को प्रोविसो। 153 ग एक काल्पनिक कथा बनाता है जिसमें तलाशी शुरू करने की तारीख तक किए गए किसी भी संदर्भ को उस तारीख तक किया गया संदर्भ माना जाता है जब तलाशी न लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या जब्त की गई संपत्ति आदि प्राप्त होती हैं। s.132 को एस में संशोधन से पहले शुरू किया गया था। 153 सी. डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015, लेखा बहियां या दस्तावेज या संपत्ति केवल तलाशी न लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जब्त की गई थी।

25.04.2017 , जो संशोधन के बाद है, इस प्रकार, जब नोटिस यू / s.153C को 04.05.2018 पर जारी किया गया था, उस तारीख को मौजूद कानून का प्रावधान, यानी, संशोधित एस। 153 सी लागू होगा इसके अलावा, एस का उद्देश्य और उद्देश्य। 153 सी को संबोधित करना है

तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि एस। 153 ग वित्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित,

2015 01.06.2015 से डब्ल्यू. ई. एफ. उन खोजों पर लागू नहीं होगा जो 01.06.2015 को एस. में लाया गया अस्थिर संशोधन माना जाता है। 153 सी यू/द्वारा की गई खोजों पर लागू होता है s.132 01.06.2015 से पहले, यानी संशोधन की तारीख-वित्त अधिनियम, 2015।

एस। 153 ग (वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित)-उद्देश्य/उद्देश्य

बताया गया है।

756 आय कर अधिकारी v. विक्रम सुजीतकुमार भाटिया

कानूनों की व्याख्या: कराधान कानून-मशीनरी प्रावधान की व्याख्या-आयोजित: अदालतें, मशीनरी की व्याख्या करते हुए

किसी कराधान कानून के प्रावधानों को अपने प्रकट उद्देश्य को इस तरह से समझकर प्रभावी बनाना चाहिए ताकि कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके। 153 अधिनियम का सी एक तंत्र प्रावधान है- इस प्रकार, संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य देखा जाना चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के प्रावधान के अनुसार, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2005 के माध्यम से जोड़ा गया है, और उक्त प्रावधान का प्रभाव यह है कि यह एक काल्पनिक कल्पना पैदा करता है जिसमें तलाशी शुरू करने की तारीख तक किया गया कोई भी संदर्भ उस तारीख तक किया गया संदर्भ माना जाता है जब तलाशी न लेने वाले व्यक्ति के निर्धारण अधिकारी को लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या जब्त की गई संपत्ति आदि प्राप्त होती हैं। इस प्रकार, तत्काल मामले में, भले ही धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की गई थी

धारा 153 सी डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 में संशोधन, लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को गैर-तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा केवल 25.04.2017 पर जब्त किया गया था, जो संशोधन के बाद है, इसलिए जब धारा 153 सी के तहत नोटिस 04.05.2018 पर जारी किया गया था, तो उस तारीख को मौजूद कानून का प्रावधान, यानी संशोधित धारा 153 सी,

लागू होता है। [पैरा 10.3] [777-ई-एफ]

1.2 . अधिनियम की धारा 153 सी एक मशीनरी प्रावधान है। द.

न्यायालयों को किसी कराधान कानून के तंत्र प्रावधानों की व्याख्या करते समय, कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए इसका इस तरह से अर्थ निकालकर इसके प्रकट उद्देश्य को प्रभावी बनाना चाहिए। [पैरा 10.6] [781-बी]

1.3 . यहाँ तक कि अपरिवर्तित एस। 153 सी संबंधित है

किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण। धारा 153 सी का उद्देश्य और उद्देश्य तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों को संबोधित करना है। यहां तक कि असंशोधित धारा 153 सी के अनुसार, अन्य व्यक्तियों (तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा) के खिलाफ कार्यवाही खाता बही या जब्त किए गए या मांगे गए दस्तावेजों की जब्ती के आधार पर की गई थी। व्यक्ति की खोज की। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने [2023] 2 एस. सी. आर. की व्याख्या की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शब्द "संबंधित" प्रतिबंधात्मक रूप से और/या संकीर्ण रूप से और जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि यद्यपि धारा 132 के तहत तलाशी कार्यवाही के दौरान किसी तीसरे पक्ष/व्यक्ति से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री पाई गई, लेकिन राजस्व ऐसे तीसरे पक्ष के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सका, जिसके कारण विधायिका/संसद को "संबंधित या संबंधित" शब्दों के स्थान पर "संबंधित या संबंधित" शब्दों को प्रतिस्थापित करके और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार नोट की गई शरारत को दूर करने के लिए स्पष्ट करना आवश्यक हो गया। इसलिए, यदि संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतिकरण का आकलन है कि इस तथ्य के बावजूद कि दोषपूर्ण सामग्री

- तलाशी लिए गए व्यक्ति के परिसर से लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या उनसे संबंधित संपत्तियों के रूप में पाए गए हैं, फिर भी उन्हें केवल इस आधार पर धारा 153 सी के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है कि तलाशी पहले की गई थी।

संशोधन के लिए, उस मामले में, धारा 153 सी में संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य स्वीकार किया जाता है, जो कि "संबंधित या संबंधित" शब्दों के "संबंधित या संबंधित" शब्दों के प्रतिस्थापन को हतोत्साहित किया जाएगा। ऐसी कोई भी व्याख्या, जो अधिनियम/संविधि के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर सकती है, न्यायालय द्वारा टाल दी जाएगी। यदि संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से प्रचार की गई व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में, धारा 153 सी का उद्देश्य और उद्देश्य भी, अर्थात् -

किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण (इसके अलावा)

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को अस्थिर माना जाता है, और इसे रद्द कर दिया जाता है और एक तरफ रख दें। संशोधन एस में लाया गया। 153 वित्त अधिनियम, 2015 के अनुसार अधिनियम, 1961 का सी अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत 01.06.2015, यानी संशोधन की तारीख से पहले की गई खोजों पर लागू होगा। [पैरा 11] [786-एफ-जी]

पेप्सिको इंडिया होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4155; शामराव बनाम। पारुलेकर बनाम जिला मजिस्ट्रेट,

(1952) 2 एससीसी 1: 1952 एस. सी. आर. 683, जिल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2004) 8 एस. सी. सी. 1; आयकर आयुक्त-3 बनाम कलकत्ता निटवियर, लुधियाना (2014) 6 आय कर अधिकारी बनाम।

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया

एस. सी. सी. 444; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, (1975) 2 एस. सी. सी. 274; लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) 7 एस. सी. सी. 653; संपदा शुल्क नियंत्रक बनाम एम. ए. मर्चेन्ट, 1989 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 499; स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज. स्टार टोबैको कंपनी, (1974) 3 एस. सी. सी. 249; गिरधारी लाल एंड संस वर्सेज. बलबीर नाथ माथुर (1986) 2 एस. सी. सी. 237; इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेज. हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स (2003) 3 एस. सी. सी. 57-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1952 एससीआर 683

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.4

(2014) 6 एस. सी. सी. 444

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.6

(1986) 2 एस. सी. सी. 237

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.7

(2003) 3 एससीसी 57

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.7

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 911

2022 .

उच्च न्यायालय के 02.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के एस. सी. ए. सं. 18777 में अहमदाबाद में गुजरात के एस.

के साथ

सिविल अपील सं। 912 , 913 , 914 , 915 , 916 , 917 , 918 , 919 , 920 , 921 ,

922 , 923 , 924 , 925 , 926 , 927 , 928 , 929 , 930 , 931 , 932 , 933 , 934 , 935 , 936 , 937 , 938,939 , 940 , 941 , 942 , 943 , 944 , 945 , 946 , 947 , 948 , 949 , 950 , 951 , 952 , 953,954 , 955 , 956 , 957 , 958 , 959 , 960 , 961 , 962 , 963 , 964 , 965 , 966 , 967,968 , 969 , 970 , 971 , 972 , 973 , 974 , 975 , 976 , 977 , 978 , 979 , 980 , 981 , 982,983,984,985 , 986 , 987 , 988 , 989 , 990 , 991 , 992 , 993 , 994 , 995 , 996 , 997 , 998 , 999 , 1000 , 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 , 1006 , 1007 , 1008 , 1009 , 1010 , 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1019 , 1020 , 1021 , 1022 , 1023 , 1024 , 1025 और 2022 का 1026।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., जोहेब हुसैन, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री.

आकांक्षा कौल, मनीष, बिजन घोष, धनंजय महापात्रा, राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आर. के. पटेल, तुषार हेमानी, केतन एच. शाह, सौरभ सोपारकर,

श्री एड. , सुश्री मनीषा टी. करिया, दर्शन आर. पटेल, सुश्री सुखदा कालरा, आदर्श कुमार, सुश्री निधि नागपाल, सुश्री वैभववी पारिख, सुश्री अदिति सेठ, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाडिया, सुश्री प्रियंका राठी, हरेश रायचुरा, [2023] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अमन के. शाह, राम भदौरिया, सुश्री सरोज रायचुरा, कल्प रायचुरा, बंदिश सोपारकर, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, आर. विष्णु कुमार, अलापति साहित्य कृष्ण, पूर्व जितेंद्र मलकन, सुधीर मेहता, सुश्री खुशबू विनोद राय मलकन, जितेंद्र मलकन, सुश्री धरिता पी मलकन, सुश्री दीपा गोरसिया, आलोक कुमार, सुश्री नंदिनी छाबड़ा, सुश्री शैली मेहता, सुश्री भावना सरकार, हार्दिक वोरा, समीर सिंह, विजय कुमार सिंह, साहिल लोचब, सुश्री नीलम सिंह, सचिन सिंह, दर्शन गांधी, जिमी पटेल, सुबोध एस. पाटिल, चित्रांशुल ए. सिन्हा, सिद्धार्थ झा, भरत कुमार शर्मा, केतन शाह, अमन शाह, रोशन संधालिया, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित आम लोगों से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 18777 और अन्य संबंधित मामलों में पारित दिनांक 02.04.2019 का निर्णय और आदेश

अन्य विशेष दीवानी आवेदनों में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित मामलों के साथ-साथ विवादित निर्णय और आदेश

उपरोक्त मामले में अपना पूर्व निर्णय, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अधिनियम, 1961" के रूप में संदर्भित) की धारा 153 सी के तहत जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया है।

-

निर्धारित-इसमें उत्तरदाता और परिणामी मूल्यांकन आदेशों (जहां मूल्यांकन पूरा हो गया था) को यह मानते हुए दरकिनार करते हुए कि अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी (वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित) संशोधन की तारीख से पहले शुरू किए गए अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी पर लागू नहीं होगी, राजस्व ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कानून का सवाल

इस न्यायालय के विचार के लिए जो उत्पन्न होता है वह है:

वित्त अधिनियम, 2015 के अनुसार अधिनियम, 1961 खोजों पर लागू होगा।
01.06.2015 से पहले अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत आयोजित,

अर्थात्, संशोधन की तिथि?

3. सुविधा के लिए, से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील

2018 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 12825 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को प्रमुख माना जाता है और माना जाता है उक्त रिट याचिका में मामले और तथ्यों का वर्णन किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं:

आय कर अधिकारी v. विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

3.1 मूल रिट याचिकाकर्ता, एक व्यक्ति ने आकलन वर्ष (ए. वाई.) के लिए अपनी आय विवरणी 11.09.2012 पर दाखिल की, जिसमें कुल आय रु. 44,73,820 / - साझेदारी फर्म से व्यावसायिक आय और अन्य आय के रूप में। एच. एन. सफल समूह के विभिन्न परिसरों में 04.09.2013 पर तलाशी ली गई। एक पंचनामा आया

07.09.2013 पर तैयार किया गया। जब्त की गई सामग्री के आधार पर, निर्धारण अधिकारी ने धारा 153 सी के तहत निर्धारिती के खिलाफ कार्यवाही शुरू की अधिनियम, 1961 के तहत दिनांक 08.02.2018 का नोटिस जारी किया गया।

3.2 निर्धारिती ने अपना जवाब दिनांक 01.05.2018 पर दाखिल किया और

केवल मूल रिट याचिकाकर्ता के नाम के संदर्भ थे, निर्धारण अधिकारी अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि अधिनियम की धारा 153 सी को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त जो तलाशी की तारीख पर थी, अर्थात्, निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि कोई भी धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या लेखा पुस्तकें या जब्त किए गए या मांगे गए दस्तावेज तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के हैं या उनके हैं, संतुष्ट नहीं थे। यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 153 सी के तहत कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से, 1961 , तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी के साथ-साथ तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वतंत्र संतुष्टि दर्ज की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि, हालांकि, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए संतुष्टि नोट के अवलोकन पर

मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले में, यह स्पष्ट था कि मूल्यांकन अधिकारी ने केवल तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि को दोहराया था और अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत अपेक्षित संतुष्टि को दर्ज नहीं किया था।

3.3 आकलन अधिकारी ने 23.07.2018 दिनांकित आदेश द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया। [2023] 2 एस. सी. आर. की अस्वीकृति से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ आपत्तियां, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की

उच्च न्यायालय के समक्ष।

3.4 अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत इसी तरह के नोटिसों को अन्य व्यक्तियों-तलाशी लेने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों में, अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत कार्यवाही के आधार पर, मूल्यांकन पूरे किए गए थे, जिन्हें चुनौती देने की भी अनुमति दी गई थी क्योंकि इसमें शामिल प्रश्न सामान्य था।

निर्धारिती के मूल अधिकारों और इसलिए, प्रक्रिया में केवल परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के दायरे का विस्तार करता है, एक निर्धारिती को लाकर यदि उससे संबंधित लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या उससे संबंधित जानकारी उस धारा के दायरे में तलाशी के दौरान जब्त की गई है, तो यह प्रश्न महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान के तथ्यों में

मामले में, तलाशी की तारीख को, यह केवल तभी था जब ऐसी सामग्री तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की थी, कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी ऐसी संतुष्टि दर्ज कर सकता था और सामग्री को ऐसे अन्य व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता था। हालांकि, तलाशी की तारीख के बाद, संशोधन को लागू कर दिया गया है और संशोधन के आधार पर, याचिकाकर्ता जिन्हें तलाशी की तारीख तक अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के दायरे में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें अब इस आधार पर इसके दायरे में लाने की मांग की जाती है कि - संशोधन लागू होने के बाद अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत संतुष्टि पत्र और नोटिस जारी किए गए हैं। इसलिए, यह देखते हुए कि अधिनियम, 1961 की संशोधित धारा 153 सी को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा और इसलिए, आयकर अधिकारी के संबंध में अधिनियम, 1961 के संशोधन के बाद धारा 153 सी के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था।

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

01.06.2015 से पहले की गई तलाशी के लिए, विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और नोटिस के साथ-साथ संबंधित मूल्यांकन आदेशों को भी रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।

4. श्री के. एम. नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने राजस्व की ओर से पेश होते हुए दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए

सामान्य निर्णय और आदेश और मूल रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत नोटिस को रद्द और अलग करते हुए-तलाशी लेने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों, उच्च न्यायालय ने उद्देश्य और उद्देश्य की उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है।

जिसके कारण अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी में संशोधन की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने हमें अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी पर ले जाया है क्योंकि यह वित्त अधिनियम, 2015 और वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किए जाने के बाद धारा 153 सी के संशोधन से पहले था, जो निम्नानुसार है:

" धारा 153 सी, जो वित्त के माध्यम से संशोधन से पहले थी

अधिनियम, 2015 इस प्रकार है:

153 - सी. किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण। (1) धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां निर्धारण अधिकारी का समाधान होता है कि कोई भी धन, सराफा,

आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या लेखा बहियां या जब्त या अधिग्रहित दस्तावेज धारा 153-ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हैं या उनके हैं, तो जब्त या अधिग्रहित लेखा बहियां या दस्तावेज या संपत्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी और वह निर्धारण अधिकारी एक-दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और उनकी आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा।

धारा 153 क के प्रावधानों के अनुसार अन्य व्यक्ति,

बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 153-ए की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132-ए के तहत मांग करने की तारीख के संदर्भ का अर्थ निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहित लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र:

आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि केंद्र सरकार नियमों द्वारा

इसके द्वारा किए गए और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट करें,

जिसे निर्धारण अधिकारी को उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के छह निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें तलाशी ली जाती है या मांग की जाती है, सिवाय उन मामलों के जिनमें कोई मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

कम हो गया है। (2) जहाँ लेखा बहियां या दस्तावेज या परिसंपत्तियाँ जब्त की जाती हैं या

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट के रूप में याचना की गई है या ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि के बाद प्राप्त की गई है जिसमें धारा 132 या मांग के तहत तलाशी ली जाती है।

धारा 132-ए के तहत और ऐसे मूल्यांकन के संबंध में किया जाता है।

वर्ष

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की कोई विवरणी नहीं दी गई है, लेकिन धारा 142 की उप-धारा (2) के तहत कोई सूचना नहीं दी गई है।

उसे जारी किया गया है, या

(ख) आय की विवरणी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है लेकिन धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत कोई सूचना नहीं दी गई है और इसके तहत सूचना देने की सीमा निर्धारित की गई है।

धारा 143 की उप-धारा (2) समाप्त हो गई है, या

(ग) मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, किया गया है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहित लेखा बहियां या दस्तावेज या परिसंपत्तियां प्राप्त करने की तारीख से पहले

ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता, ऐसे निर्धारण अधिकारी

नोटिस जारी करेगा और इस तरह से ऐसे निर्धारण वर्ष के ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा धारा 153-ए में उपबंध किया गया है।

वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित किए जाने के बाद अधिनियम की धारा 153 सी,

15 इस प्रकार पढ़ता है:

153 - सी. किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण। — (1)

धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां

निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि, एम. ई. कर अधिकारी v.

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया

[एम. आर. शाह, जे.]

((क) कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या

जब्त या अधिग्रहित वस्तु, जिसका है; या

((ख) जब्त की गई कोई लेखा बहियां या दस्तावेज, या

मांग की गई, संबंधित या संबंधित, या कोई जानकारी

इसमें निहित, से संबंधित है,

धारा 153-क में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, तब जब्त या अधिगृहीत लेखा बहियां या दस्तावेज या परिसंपत्तियां निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी।

ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाला और वह निर्धारण अधिकारी एक-दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा और धारा 153-क के प्रावधानों के अनुसार दूसरे व्यक्ति की आय का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नोटिस जारी करेगा, यदि -

निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि लेखा बहियां या

जब्त या अधिग्रहित दस्तावेजों या परिसंपत्तियों का ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के निर्धारण पर असर पड़ता है।

मूल्यांकन से तुरंत पहले छह मूल्यांकन वर्ष

उस पूर्ववर्ष से सुसंगत वर्ष जिसमें तलाशी ली जाती है या मांग की जाती है और धारा 153-ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए:

बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 153-ए की उप धारा (1) के दूसरे परंतुक में धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132-ए के तहत मांग करने की तारीख के संदर्भ का अर्थ निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहित लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र:

बशर्ते कि केंद्र सरकार नियमों द्वारा इसके द्वारा किए गए और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट करें,

जिसे निर्धारण अधिकारी को उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के छह निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसमें खोज की जाती है या मांग की जाती है और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। धारा 153-क की उप-धारा (1) में, उन मामलों को छोड़कर जहां

किसी भी मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में कमी आई है।

23] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियों या दस्तावेजों या संपत्तियों को अभिगृहीत या अधिगृहीत किया गया है या उन पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया है।

पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि के बाद अन्य व्यक्ति जिसमें धारा 132 के तहत तलाशी ली जाती है या धारा 132-ए के तहत मांग की जाती है और ऐसे निर्धारण के संबंध में

वर्ष

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है और धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना नहीं दी गई है।

उसे जारी किया गया है, या

(ख) आय की विवरणी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है, लेकिन धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत कोई सूचना नहीं दी गई है।

धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस देने की सीमा समाप्त हो गई है, या

(ग) मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, किया गया है।

ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिगृहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख से पहले, ऐसा निर्धारण अधिकारी नोटिस जारी करेगा और ऐसे निर्धारण वर्ष के ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करेगा।

धारा 153-ए में उपबंध किया गया है।

4.1 श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि धारा 153 सी में संशोधन दिल्ली के अवलोकन को देखते हुए आवश्यक था।

पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4155 के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि "संबंधित या संबंधित" शब्दों को "संबंधित या संदर्भित" शब्दों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, पहला शब्द बाद वाले की तुलना में बहुत संकीर्ण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस प्रावधान को तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक कि दस्तावेज/सामग्री तीसरे पक्ष (तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा) से संबंधित न हो। ऐसी स्थिति में, जहां धारा 132 के तहत तलाशी कार्यवाही के दौरान किसी तीसरे पक्ष से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी, राजस्व दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए ऐसे तीसरे पक्ष के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय का उक्त अवलोकन उस शरारत को दबाने के रास्ते में आ रहा था जिसे विधायिका ने आयकर अधिकारी v.

दबाएँ। इसलिए, वित्त अधिनियम, 2015, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 के अनुसार, जहां तक लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों का संबंध है, धारा 153 सी को "संबंधित या संबंधित" शब्दों को "संबंधित या संबंधित" शब्दों के साथ बदलने के लिए प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधित किया गया है।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि "संबंधित या संबंधित" और "संबंधित या संबंधित" शब्दों या वाक्यांशों के बीच अंतर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "संबंधित या संबंधित" शब्द "संबंधित या संबंधित" की तुलना में बहुत व्यापक महत्व के हैं। इसलिए, विधायिका ने स्थिति को शामिल करने के लिए धारा 153 सी के संचालन के दायरे का विस्तार किया है।

जहां अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी कार्यवाही के दौरान, यदि किसी तीसरे पक्ष से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज/सामग्री पाई जाती है, तो राजस्व ऐसे तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

4.3 इसके बाद राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री नटराज ने प्रस्तुत किया कि वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 153 सी में संशोधन की व्याख्या करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों/परीक्षणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है:

((i) प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन का प्रभाव;

(@ (ii) विधायी आशय; (@iii) (@iv) व्याख्या की धारा 153 सी

अधिनियम, 1961 एक मशीनरी प्रावधान है;
जो कानून या उसका एक हिस्सा "मृत" बनाता है।

पत्र "से बचा जाना चाहिए;

(v)

कानून बनाने की शक्ति में पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति शामिल है।

4.4 उपरोक्त के बारे में विस्तार से बताते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक धारा 153 सी में संशोधन के प्रभाव का संबंध है, धारा 153 सी "प्रतिस्थापन" के माध्यम से संशोधित, वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 जिसके तहत शब्द "संबंधित या संबंधित" हैं

"संबंधित या संबंधित" द्वारा प्रतिस्थापित। कि यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि प्रतिस्थापन के माध्यम से किया गया कोई भी संशोधन मूल अधिनियम की तारीख से संबंधित है। शामराव वी. पारुलेकर बनाम जिले के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है। मजिस्ट्रेट, (1952) 2 एससीसी 1: 1952 एससीआर 683। कि उक्त निर्णय में, यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिस्थापन द्वारा एक संशोधन का प्रभाव कानून पुस्तिका से पहले के प्रावधान को मिटा देने और इसे संशोधित प्रावधान के साथ बदलने का है जैसे कि अपरिवर्तित प्रावधान कभी मौजूद

नहीं था। इसलिए, कानून, जो इस मामले में अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी है, को इस तरह पढ़ना होगा जैसे कि संशोधित प्रावधान [2023] 2 एस. सी. आर. से मौजूद था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुत शुरुआत। श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने भी जिल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2004) 8 एस. सी. सी. 1 (पैरा 24 और 25) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

4.5 यह तर्क दिया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 153 सी में संशोधन की व्याख्या करते हुए भी, इसके पीछे विधायी इरादे

संशोधन पर विचार किया जाना आवश्यक है। कि किसी कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय को उस इरादे को ध्यान में रखना चाहिए जिसके साथ कानून पारित किया गया था और उस शरारत को दबाने की कोशिश की गई थी। कि वह व्याख्या जो विधायिका के इरादे को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करती है, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कि वर्तमान मामले में, विधायिका का इरादा धारा 153 सी के दायरे में उन व्यक्तियों को लाना था जिनके खिलाफ धारा 132 के तहत तलाशी की कार्यवाही के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के परिसर में आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है। हालाँकि, "संबंधित या संबंधित" शब्दों को दिए गए संकीर्ण दायरे ने इस उद्देश्य को विफल कर दिया और इसलिए, संशोधन की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विधायी इरादे और शरारत को ध्यान में रखते हुए, संशोधित धारा 153 सी के अलावा कोई भी व्याख्या

यह सभी लंबित और भविष्य की कार्यवाही पर लागू होता है, भले ही अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी पहले या बाद में की गई हो। संशोधन, विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में विफल रहेगा। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने ज़िले सिंह (उपरोक्त) (पैरा 14, 15, 18 और 20) और गिरधारी लाल एंड संस बनाम. वीर नाथ माथुर (1986) 2 एस. सी. सी. 237 के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

4.6 उपरोक्त दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि उस शरारत और दोष को दूर करने के लिए संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने और ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिसके लिए संशोधन की आवश्यकता थी। जैसा कि देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार संसद के इरादे का पता चल जाने के बाद और कानून के उद्देश्य और उद्देश्य का पता चल जाने के बाद, यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह कानून को एक उद्देश्यपूर्ण या कार्यात्मक व्याख्या दे।

4.7 श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी एक मशीनरी प्रावधान है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में यह भी कहा है कि धारा 153 सी एक तंत्र प्रावधान है। व्याख्या करते हुए ए

एक कराधान कानून के मशीनरी प्रावधान, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने प्रकट उद्देश्य को प्रभावी बनाए। कानून के उद्देश्य को विफल करने वाली व्याख्या से बचा जाना चाहिए। कि आय कर अधिकारी V द्वारा अवलोकन के बावजूद।

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

उच्च न्यायालय कि अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी एक तंत्र प्रावधान है, उच्च न्यायालय इसके पीछे के उद्देश्य को प्रभावी बनाने में विफल रहा है। आयकर आयुक्त-III बनाम कलकत्ता निटवियर, लुधियाना (2014) 6 एस. सी. सी. 444 (पैरा 32 और 34) के मामले में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया है।

4.8 इसके बाद श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार, कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और ऐसी किसी भी व्याख्या से बचना चाहिए जो कानून या इसके एक हिस्से को "मृत पत्र" बनाती है। कि अपनाया गया निर्माण अनुरूप होगा

कानून के अन्य प्रावधानों के साथ। कि स्थापित कानून के अनुसार, अदालतों को संघर्ष में कानूनों को सुसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रावधान का उपयोग दूसरे के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस पृष्ठभूमि में, धारा 153 सी के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि उत्तरदाताओं का यह तर्क कि संशोधित धारा 153 सी संशोधन से पहले की गई तलाशी पर लागू नहीं होगी, तो इन शब्दों के पीछे का उद्देश्य "यदि वह निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि जब्त की गई लेखा बहियों या दस्तावेजों या संपत्तियों का उस पिछले वर्ष से ठीक पहले छह मूल्यांकन वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के निर्धारण पर असर पड़ता है जिसमें तलाशी ली जाती है या

माँग की जाती है और धारा 153 क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए विफल कर दिया जाएगा। कि यह हमेशा माना जाता है कि विधायिका एक हाथ से वह नहीं लेगी जो वह दूसरे हाथ से देती है। उपरोक्त के समर्थन में, आयकर आयुक्त बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स, (2003) 3 एस. सी. सी. 57 (पैरा 17 से 21) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी कानून बनाने की शक्ति

इसमें पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति शामिल है। कि यह अच्छी तरह से तय है कि विधायिका पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने के लिए अच्छी तरह से सक्षम है। हालाँकि, किसी अधिनियम की पूर्वव्यापीता की धारणा नहीं की जा सकती है, लेकिन यह स्पष्ट अधिनियम के माध्यम से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, यदि विधायिका सक्षम है और कानून के दायरे का विस्तार करने के लिए विधायिका का इरादा एकत्र किया जा सकता है, चाहे वह स्पष्ट रूप से हो या आवश्यक निहितार्थ, उसी को प्रभावी किया जाएगा। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम हिंदुस्तान मशीन के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है।

टूल्स लिमिटेड, (1975) 2 एस. सी. सी. 274 (पैरा 10) और लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) 7 एस. सी. सी. 653 (पैरा 21)।

23] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.10 श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि उत्तरदाताओं के पास एक "निहित स्वार्थ" है।

"अधिकार" और अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी में संशोधन उत्तरदाताओं के ऐसे निहित मूल अधिकार को प्रभावित करता है। कि ऐसा कोई मूल अधिकार उत्तरदाताओं में निहित नहीं है। एक बार जब धारा 153 सी में उल्लिखित शर्तों को पूरा कर लिया जाता है, तो कोई भी दायित्व वास्तविक रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारियों ने कारणदर्शक नोटिस जारी किया और उसके बाद कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उत्तरदाताओं के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, कारण दर्शाएँ नोटिस के प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है।

4.11 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित धारा 153 सी, हालांकि एक तंत्र प्रावधान है, केवल धारा 153 सी में संशोधन के बाद शुरू की गई तलाशी कार्यवाही पर लागू होगी।

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, संबंधित निर्धारिती की ओर से पेश वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि अपीलों के वर्तमान समूह में विवाद खोज मामलों में मौजूदा कानून की प्रयोज्यता के बिंदु के संबंध में है, अर्थात्, क्या अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी, जिसे 01.06.2015 से संशोधित किया गया है, उन मामलों में लागू होगी जहां उस तारीख से पहले तलाशी शुरू की जाती है।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि 01.06.2015 से, यानी, तलाशी की तारीख के बाद, लेकिन धारा 153C नोटिस जारी करने से पहले, कानून में संशोधन किया गया है।

आकलनकर्ताओं के एक नए समूह को शामिल करने के लिए खोज द्वारा कवर किए गए तीसरे पक्ष के दायरे का विस्तार करने के लिए अधिनियम, 2015। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संशोधन के आधार पर, अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें प्रावधान के दायरे में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह तलाशी की तारीख पर था।

5.2 इसे आगे संबंधित निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत किया जाता है।

कि विभाग की ओर से यह मामला है कि अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी एक प्रक्रियात्मक और मशीनरी प्रावधान है, संशोधन, हालांकि 01.06.2015 से प्रभावी है, पूर्वव्यापी है और इस प्रकार, आय कर अधिकारी v.

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

उन मामलों पर लागू होता है जहां संशोधन से पहले तलाशी ली गई थी, लेकिन अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत नोटिस संशोधन के बाद जारी किए गए हैं। विभाग की ओर से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन निहित अधिकारों को नहीं छीनता है, और इसलिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। विभाग की ओर से आगे यह तर्क दिया जाता है कि तलाशी की तारीख अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के लिए प्रासंगिक नहीं है और संशोधित प्रावधान लागू होगा क्योंकि संतुष्टि नोट और अधिकार क्षेत्र की धारणा दोनों आई. डी. 1 के बाद के थे। विभाग की उपरोक्त दलीलों के संबंध में, संबंधित निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक तंत्र प्रावधान जो प्रभावित करता है मूल अधिकारों को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। यद्यपि अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी एक तंत्र प्रावधान है, संशोधन को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है।

5.3 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, हालांकि प्रावधान मशीनरी प्रावधान हैं, संशोधन लाता है

मूल अधिकार और इसलिए, लागू नहीं किए जा सकते हैं पीछे की ओर। उनके निवेदन के समर्थन में कि संशोधन

499. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने संपत्ति शुल्क अधिनियम की नई धारा लागू होने की तारीख से पहले पूरा किए गए मूल्यांकन को फिर से खोलने की अनुमति देकर निहित अधिकारों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। 5.4 यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 153 सी में संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के दायरे में आता है, ऐसे निर्धारिती, जो अब तक इसके दायरे में नहीं आए थे, यानी वे व्यक्ति जिनके लिए लेखा पुस्तकें/दस्तावेज संबंधित हैं या संबंधित हैं, न कि केवल वे व्यक्ति जिनके साथ वे संबंधित हैं। कि यह विस्तार, इस प्रकार, मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, क्योंकि नए निर्धारकों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा सकती है और इसलिए एम. ए. के मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

मर्चेट (उपरोक्त) को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से लागू किया गया है।

5.5 यह आगे तर्क दिया जाता है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रक्रियात्मक भी

कानून पर्याप्त अधिकार प्रदान करते हैं और ऐसे अधिकारों को प्रभावित करने वाले संशोधनों को संभावित माना गया है। उस पुनः खोलने को शक्ति का प्रश्न माना गया है न कि प्रक्रिया का जैसा कि इस न्यायालय द्वारा [2023] 2 एस. सी. आर. में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु राज्य बनाम स्टार टोबैको कंपनी, (1974) 3 एस. सी. 249 का मामला।
5.6 इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी में संशोधन ने कर निर्धारकों का एक नया वर्ग जोड़ा है और न केवल मौजूदा कर निर्धारकों के लिए प्रक्रिया को बदला है, इसलिए यह नहीं दिया जा सकता है

पूर्वव्यापी प्रभाव। कि उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी में संशोधन केवल प्रक्रिया प्रावधान में परिवर्तन नहीं है जो पहले से ही कवर किए गए निर्धारिती को प्रभावित करता है। निर्धारिती के एक नए वर्ग को अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत लाने की मांग की गई है, जो निर्धारिती के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। तलाशी की तारीख के बाद, ऐसे निर्धारिती, जिन्हें तलाशी की तारीख तक अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के दायरे में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें अब इसके दायरे में लाने की मांग की जाती है।

5.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 01.06.2015 से पहले, मूल्यांकन अधिकारी केवल संतोष दर्ज कर सकता था कि क्या जब्त की गई सामग्री यह दूसरे व्यक्ति का है। कि वर्तमान मामले में, चूंकि हार्ड डिस्क, जो तलाशी लेने वाले व्यक्तियों से मिली थी, खोज की तारीख को उत्तरदाताओं की नहीं थी, इसलिए अधिनियम की धारा 153 सी के तहत अधिकार क्षेत्र मौजूद नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से कहा गया है कि यदि 2013 में तलाशी की तारीख को, सामग्री को तलाशी लेने वाले व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस आधार पर अग्रेषित किया गया था कि यह उत्तरदाताओं-कर निर्धारकों की है, तो अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने के खिलाफ चुनौती सफल होती, क्योंकि सामग्री वास्तव में प्रतिवादी की नहीं है। कि इसके अलावा, एक बार एक संतुष्टि बनाई और

सामग्री को अग्रेषित करते हुए, तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा एक बार फिर के आधार पर संतुष्टि पैदा करने का कोई सवाल ही नहीं है

निर्माण का संभावित नियम लागू होगा। यह कि जैसा कि जिल सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है, यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक कानून प्रथम दृष्टया संभावित है। जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक

निहितार्थ द्वारा नहीं किया जाता है। नियम सामान्य रूप से लागू होता है जहां वस्तु आय कर अधिकारी VI

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

विधायिका ने खोज की तारीखों पर विचार किया और निर्दिष्ट किया कि यह प्रावधान 31.05.2003 के बाद किए गए खोज कार्यों पर लागू होता है। इसलिए, धारा 153 ए और 153 सी को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और संबंधित तिथि खोज की तारीख होनी चाहिए जैसा कि वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

5.9 निर्धारिती की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि संतुष्टि भी तुरंत दर्ज नहीं की गई है। कि तलाशी लिए गए व्यक्ति ने निपटान आयोग के समक्ष आवेदन दायर किया था

30.01.2015 और याचिकाकर्ताओं से हार्ड डिस्क के आधार पर धन की प्राप्ति स्वीकार की। निपटान आवेदन की प्रति निर्धारण अधिकारी को दी जानी चाहिए। तदनुसार, तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी के पास कथित धन भुगतान के बारे में जानकारी होगी।

याचिकाकर्ताओं को 30.01.2015 पर, यदि पहले नहीं, जबकि दस्तावेजों को 25.04.2017 पर स्थानांतरित किया गया था। इसलिए, दस्तावेजों को तथ्यों के बारे में जानकारी के 2 साल और 3 महीने बाद स्थानांतरित किया गया था, जिसके आधार पर धारा 153 सी की कार्यवाही शुरू की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कलकत्ता निटवियर, लुधियाना (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए इसकी अनुमति नहीं है।

5.10 सिविल अपील सं. में निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। 1019 , 997 , 1016 , 1021 और 2022 के 1023 ने उपरोक्त के अलावा, आगे प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाताओं-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए विभिन्न आधार उठाए थे कि धारा 153 सी के तहत जारी किए गए नोटिस खराब और अवैध थे। हालांकि, यह

उच्च न्यायालय ने 2018 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 12825 और अन्य में निर्णय का पालन किया है और निर्णय लेकर रिट याचिकाओं को अनुमति दी है।

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में केवल एक सवाल और शेष मुद्दे अनिश्चित छोड़ दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि यह माननीय न्यायालय [2023] 2 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्व द्वारा अपील की अनुमति देने के लिए, मामलों को नोटिसों और अन्य मुद्दों की वैधता पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जा सकता है जिन्हें मूल रूप से अनिश्चित छोड़ दिया गया था।

5.11 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रार्थना की जाती है -

निर्धारित कि वर्तमान अपीलों को खारिज किया जाए।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

7. इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न

यह है:

" क्या वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी में लाया गया संशोधन लागू होगा

अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत पहले की गई तलाशी

01.06.2015 , अर्थात्, संशोधन की तिथि? "

8. उपरोक्त प्रश्न और प्रस्तुतियों पर विचार करते समय

संबंधित पक्षों की ओर से दिए गए कुछ तथ्य, जो प्रश्न के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं, को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो नीचे दिए गए हैं:

कि अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत एक तलाशी थी

((i)

04.09.2013 पर एक एच. एन. सफल समूह के विभिन्न परिसरों में आयोजित किया गया। जब तलाशी ली गई, तब धारा 153 सी (2015 के संशोधन से पहले) थी

लागू होता है।

धारा 153 सी, जो उस समय थी, ने यह प्रावधान किया कि "इसके बावजूद

((ख)

धारा 139,147,148,149,151 और 153 में निहित कोई भी बात, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या लेखा बहियां या जब्त किए गए या मांगे गए दस्तावेज धारा 153-ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हैं या उनके हैं, तो जब्त या मांगी गई लेखा बहियां या दस्तावेज या संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएगी और निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य

व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और धारा 153ए के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा। इसने आगे यह भी प्रदान किया कि कर अधिकारी V.

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 153-ए की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132-ए के तहत मांग करने की तारीख के संदर्भ का अर्थ ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहित लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ के रूप में किया जाएगा। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री/दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। ऐसी जब्त की गई सामग्री के सत्यापन पर, यह देखा गया कि कुछ दस्तावेज इसमें प्रतिवादी से संबंधित/संबंधित हैं, जो तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य हैं। तदनुसार, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस सीमा तक संतुष्टि दर्ज की गई थी

उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं (खोजे गए व्यक्ति के अलावा) के संबंध में व्यक्ति को 25.04.2017 पर खोजा गया। कि आपत्तिजनक सामग्री के साथ उक्त संतुष्टि पत्र को 25.04.2017 पर तलाशी न लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया गया था। कि, इसके बाद, उत्तरदाताओं के मूल्यांकन अधिकारी (गैर-तलाशी)

व्यक्ति) जब्त की गई सामग्री का सत्यापन करने के बाद, उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सामग्री और नकद प्रविष्टियां मिलीं, जिन्हें दाखिल किए गए मूल विवरण में घोषित नहीं किया गया था। तदनुसार, उत्तरदाताओं के मूल्यांकन अधिकारी ने अपनी स्वतंत्र संतुष्टि दर्ज की और 04.05.2018 पर धारा 153C के तहत नोटिस जारी किया।

इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस बीच, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 153 सी में संशोधन किया गया। डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 और शब्द "संबंधित या संबंधित"

"संबंधित या संबंधित" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार, उस समय जब तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा 25.04.2017 पर और साथ ही उत्तरदाताओं के मूल्यांकन अधिकारी (गैर-तलाशी लिए गए व्यक्तियों) द्वारा 04.05.2018 पर संतुष्टि पत्र दर्ज किया गया, धारा 153C (वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित W. E. F. 01.06.2015) लागू हो गई। तलाशी न लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 153 सी के तहत नोटिस

तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री का आधार [2023] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. एन. सफल ग्रुप (तलाशी लेने वाला व्यक्ति) के विभिन्न परिसरों में और मूल्यांकन आदेश विषय थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील।

9. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न है, "क्या धारा में संशोधन लाया गया है। 153 आयकर अधिनियम, 1961 का सी वित्त अधिनियम, 2015 के अनुसार अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत की गई तलाशी पर लागू होगा, इससे पहले कि 01.06.2015, यानी संशोधन की तारीख पर विचार किया जाना आवश्यक है।

10. उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय, धारा 153 सी में संशोधन का कारण और उद्देश्य और उद्देश्य प्रस्तुत किया गया। वित्त अधिनियम, 2015 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 पर विचार करना आवश्यक है।

10.1 जैसा कि ऊपर देखा गया है, पूर्व-संशोधित धारा 153 सी में उपयोग किए गए शब्द किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित या संबंधित थे।

व्यक्ति की खोज की। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने "संबंधित" अभिव्यक्ति की व्याख्या की और कहा कि एक अंतर और अंतर है।

"संबंधित" और "संबंधित" के बीच। यह देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि परिसर से जब्त किए गए पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर

व्यक्ति की खोज करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विक्रेता का है। इसलिए, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण ने अभिव्यक्ति/शब्द "से संबंधित" को एक बहुत ही संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया और कहा कि

धारा 153 सी के तत्व संतुष्ट नहीं हुए हैं। पेप्सिको के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के आधार को हटाने के लिए

इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त), अब, धारा 153 सी को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 के स्थान पर "संबंधित या संबंधित" शब्दों को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया।

जहाँ तक लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों का संबंध है, वे "शब्दों के साथ" से संबंधित या संबंधित हैं। इस प्रकार, यह पाए जाने पर कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि यद्यपि धारा 132 के तहत तलाशी कार्यवाही के दौरान तीसरे पक्ष से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री पाई गई, लेकिन राजस्व तीसरे पक्ष के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सका, यह देखा गया कि उपरोक्त निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्त टिप्पणी उस शरारत को दबाने के रास्ते में आ रही थी जिसे विधायिका दबाने का इरादा रखती थी, जिसके कारण धारा 153 सी में संशोधन की आवश्यकता थी। इस प्रकार, यह संशोधन के माध्यम से शब्दों के प्रतिस्थापन का मामला है।

आय कर अधिकारी v. विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

10.2 इस स्तर पर, अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के पहले परंतुक को संदर्भित करने की आवश्यकता है। धारा 153 सी का पहला परंतुक

अधिनियम, 1961 को वित्त अधिनियम, 2005 के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान है कि धारा 153-ए की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132-ए के तहत मांग करने की तारीख के संदर्भ का अर्थ निम्नलिखित पुस्तकों को प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ के रूप में किया जाएगा: ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहित खाता या दस्तावेज या संपत्ति। वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित धारा 153 सी का प्रावधान इस प्रकार है:

" बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या शुरू करने की तारीख का संदर्भ

धारा 153-ए की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में धारा 132-ए के तहत मांग का अर्थ यह समझा जाएगा कि इस पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहित लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख का संदर्भ दिया गया है।

ऐसा दूसरा व्यक्ति "।

10.3 इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित धारा 153 सी के प्रावधान के अनुसार और उक्त प्रावधान का प्रभाव यह है कि यह एक काल्पनिक कल्पना पैदा करता है जिसमें तलाशी शुरू करने की तारीख तक किए गए किसी भी संदर्भ को उस तारीख तक किया गया संदर्भ माना जाता है जब तलाशी न लिए गए व्यक्ति के निर्धारण अधिकारी को लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या जब्त की गई संपत्ति आदि प्राप्त होती हैं। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, हालांकि

धारा 132 के तहत तलाशी धारा 153 सी डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2015 में संशोधन से पहले शुरू की गई थी, लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या संपत्तियों को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा केवल 25.04.2017 पर जब्त किया गया था, जो संशोधन के बाद है, इसलिए, जब धारा 153 सी के तहत नोटिस 04.05.2018 पर जारी किया गया था, उस तारीख को मौजूद कानून का प्रावधान, यानी संशोधित धारा 153 सी लागू होगी।

10.4 जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 153 सी को प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधित किया गया है जिसके द्वारा "संबंधित या संबंधित" शब्दों को "संबंधित या संबंधित" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जैसा कि इस न्यायालय ने शामराव वी. पारुलेकर (उपर्युक्त) के मामले में कहा और अभिनिर्धारित किया कि प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन का प्रभाव कानून की पुस्तक से पहले के प्रावधान को समाप्त करने और इसे संशोधित प्रावधान से बदलने का है जैसे कि अपरिवर्तित प्रावधान कभी मौजूद नहीं था। [2023] 2 एस. सी. आर. में बाद के निर्णय में

ज़िले सिंह (ऊपर) के अनुसार, इसे पैरा 24 और 25 में इस रूप में देखा गया है

" 24. एक पाठ का दूसरे पूर्व-विद्यमान पाठ के लिए प्रतिस्थापन है में नियोजित ज्ञात और
अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथाओं में से एक

" किसी मौजूदा प्रावधान का "अधिक्रमण" या केवल निरसन। 25. किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले वाले को निरस्त कर दिया जाता है।

मिल्स एसोसिएशन। वी. उत्तर प्रदेश राज्य [(2002) 2 एस. सी. सी. 645], राजस्थान राज्य बनाम। मंगीलाल पिंडवाल [(1996) 5 एस. सी. सी. 60], कोटेश्वर विट्ठल कामत बनाम। के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी [(1969) 1 एससीसी 255] और A.L.V.R.S.T. वीरप्पा चेट्टियार बनाम. एस. माइकल [ए. आई. आर. 1963 एससी

बल में था। कोटेश्वर मामले में [(1969) 1 एस. सी. सी. 255] एक तीन-न्यायाधीश

" एक नियम का "अधिक्रमण" और एक नियम का "प्रतिस्थापन" और यह अभिनिर्धारित किया कि

अपने स्थान पर अस्तित्व "।

10.5 उक्त निर्णय में, पैराग्राफ 14,15,18 और 20 में पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा के साथ, यह निम्नानुसार देखा गया है:

" 14. पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा नहीं है घोषणात्मक कानूनों पर लागू। इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करने में, रूप के बजाय सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोई नया अधिनियम पहले के अधिनियम की "व्याख्या" करने के लिए है, तो यह कर अधिकारी V.

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

बिना वस्तु के होगा जब तक कि पूर्वव्यापी रूप से इसका अर्थ न लगाया जाए। अ. व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने के लिए पारित किया जाता है।

या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करना। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई कानून उपचारात्मक है या केवल घोषणात्मक है

पूर्ववर्ती कानून का पूर्वव्यापी संचालन आम तौर पर अभिप्रेत है। एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध रूप से घोषणात्मक हो सकता है जो पहले से ही निहित था। इस प्रकृति के एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा (आईबीआईडी)।, पीपी। 468-69) .

15. हालांकि पूर्वव्यापीता को अनुमानित नहीं किया जाना चाहिए और बल्कि वहाँ है

पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा है, केज़ (कानून कानून, 7 वीं संस्करण) के अनुसार, यह विधायिका के लिए पूर्वव्यापी संचालन वाले कानूनों को लागू करने के लिए खुला है। यह स्पष्ट अधिनियमन या नियोजित भाषा से आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह नियोजित भाषा से एक आवश्यक निहितार्थ है कि

विधायिका का उद्देश्य एक विशेष खंड का पूर्वव्यापी होना था

ऑपरेशन, अदालतें इसे इस तरह का ऑपरेशन देंगी। पूर्वव्यापी कार्रवाई के स्पष्ट रूप से दिए जाने के अभाव में, अदालतों से प्रावधानों का अर्थ निकालने और इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जा सकता है कि क्या विधायिका ने कानून को पूर्वव्यापी देते हुए उस इरादे को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया था। चार कारकों को प्रासंगिक के रूप में सुझाया गया है: (i) कानून का सामान्य दायरा और कार्यक्षेत्र; (ii) जिस उपाय को लागू करने की मांग की गई थी; (iii) कानून की पूर्व स्थिति; और (iv) विधायिका ने जिस पर विचार किया था। (पी। 388) पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम से सुरक्षा के लिए विस्तार नहीं करता है निरसन का प्रभाव, एक विशेषाधिकार जो अर्जित अधिकार के बराबर नहीं था। (पी। 392)

XXXXXXX

18. राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में।

मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ [(2003) 5 एस. सी. सी. 23] का आयोजन किया गया है।

कि विधायी अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है

एक अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने का इरादा। प्रत्येक विधान, चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, विधायी क्षमता के प्रश्न के अधीन होना चाहिए। पीछे की ओर देखने की क्षमता है कुछ टचस्टोन पर निर्णय लिया जा सकता है जैसे कि: (i) उपयोग किए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट प्रदान करना चाहिए या स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए।

आर।

संचालन; (ii) पूर्वव्यापीता उचित होनी चाहिए और नहीं

अत्यधिक या कठोर, अन्यथा यह असंवैधानिक के रूप में निरस्त होने का जोखिम उठाता है; (iii) जहां न्यायिक निर्णय को दूर करने के लिए कानून पेश किया जाता है, निर्णय के वैधानिक आधार को हटाए बिना निर्णय को नष्ट करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। एक मूल वैधानिक परिवर्तन के साथ एक मान्य खंड केवल उन तरीकों में से एक है जो अपरिवर्तित कानून के तहत कार्यों को अस्थिर, निर्बाध छोड़ देते हैं। नतीजतन, एक मान्य खंड की अनुपस्थिति अपने आप में वैधानिक प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, यदि ऐसी पूर्वव्यापीता है

अन्यथा स्पष्ट।

XXXXXXX

. बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य [(1955) 2 एससीआर 03: ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661], हेडन मामला [(1584) 3 सह प्रतिनिधि 7 ए: 76 आर 637] को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। उनके प्रभुओं ने कहा है: (एससीआर

ओ. ओ. 632-33)

" यह दृढ़ता से कानून के निर्माण का एक ठोस नियम है।

इंग्लैंड में 1584 में स्थापित किया गया जब हेडन मामला [(1584) 3 सह प्रतिनिधि 7a: 76 ई. आर. 637] तय किया गया था कि

‘ सामान्य रूप से सभी कानूनों की निश्चित और सही व्याख्या के लिए (चाहे वे दंडात्मक हों या लाभकारी, प्रतिबंधात्मक या सामान्य कानून का विस्तार) चार चीजों को समझा जाना चाहिए और माना जाता है

1 सेंट. बनाने से पहले सामान्य कानून क्या था

एक्ट करें।

2 एन. वह क्या शरारत और दोष था जिसके लिए

सामान्य कानून प्रदान नहीं करता है।

3 आर. डी. संसद ने कौन सा उपाय हल किया है और नियुक्त किया है

राष्ट्रमंडल की बीमारी का इलाज करने के लिए, और

4 टी. उपचार का वास्तविक कारण; और फिर सभी न्यायाधीशों का कार्यालय हमेशा ऐसा निर्माण करना है जो शरारत को दबाना, और उपचार को आगे बढ़ाना, और शरारत को जारी रखने के लिए सूक्ष्म आविष्कारों और टालमटोल को दबाना, और निजी सामान के लिए, और इलाज में बल और जीवन जोड़ना आय कर अधिकारी VI।

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

और उपाय, निर्माताओं के सच्चे इरादे के अनुसार

एक्ट, प्रो बोनो पब्लिक '।

10.6 राजस्व की ओर से यह मामला है कि धारा 153 सी एक मशीनरी प्रावधान है, जिसे इस उद्देश्य से जोड़ा गया है -

अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों का मूल्यांकन करना। यहां तक कि विवादित फैसले में और

आदेश में, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19.4 में दर्ज किया है कि अधिनियम की धारा 153 सी एक तंत्र प्रावधान है। कानून की तय स्थिति के अनुसार, न्यायालयों को किसी कर कानून के तंत्र प्रावधानों की व्याख्या करते समय, इसके प्रकट उद्देश्य को इस तरह से समझना चाहिए ताकि कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके। कलकत्ता निटवियर्स, लुधियाना (ऊपर) के मामले में, अनुभाग की व्याख्या करते हुए

158 बी. डी. (जिसे धारा 153 सी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है), इस न्यायालय ने पैरा 18,32 और 34 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

" 18. अधिनियम की धारा 158-बी. सी. और 158-बी. डी. मशीनरी प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 158-बी. सी. खंड निर्धारण के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 158-बी. डी. किसी अन्य व्यक्ति की अधोषित आय के मामले में निर्धारण के लिए प्रदान करती है। उक्त धाराएँ इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और इसलिए, उन्हें निकाला जाता है। वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

" 158 - ब्लॉक मूल्यांकन के लिए BC.Procedure। कहाँ?

धारा 132 के तहत कोई तलाशी ली गई है या लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या संपत्तियों की मांग की गई है।

धारा 132-क, किसी भी व्यक्ति के मामले में, तब

((क) निर्धारण अधिकारी

(i) 30 जून, 1995 के बाद लेकिन 1 जनवरी, 1997 से पहले शुरू की गई तलाशी या लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस भेजें जिसमें उसे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

पंद्रह दिनों से कम नहीं होना;

((ii) 1 जनवरी, 1997 को या उसके बाद शुरू की गई तलाशी या लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस भेजें जिसमें उसे पंद्रह दिनों से कम समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

लेकिन पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं,

जैसा कि सूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है कि निर्धारित प्रपत्र में विवरणी दी जाए और खंड [2023] 2 एस. सी. आर. के तहत विवरणी के रूप में उसी तरीके से सत्यापित की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i) खंड अवधि के लिए अघोषित आय सहित उसकी कुल आय का उल्लेख करते हुए धारा 142 की उप-धारा (1):

बशर्ते कि धारा 148 के तहत किसी भी नोटिस की आवश्यकता नहीं है

इस अध्याय के अधीन कार्यवाही के प्रयोजन के लिए जारी किया गया:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जिसने इस खंड के तहत विवरणी प्रस्तुत की है, वह संशोधित विवरणी दाखिल करने का हकदार नहीं होगा। (ख) निर्धारण अधिकारी खंड अवधि की अघोषित आय का निर्धारण धारा 158-बी. बी. और धारा 142 के उपबंधों में निर्धारित तरीके से करेगा।

धारा 143 की धारा (2) और (3), धारा 144 और धारा

145 जहाँ तक हो सके, लागू होगा;

(ग) मूल्यांकन अधिकारी, अज्ञात के निर्धारण पर

इस अध्याय के अनुसार खंड अवधि की आय,

निर्धारण का आदेश पारित करेगा और देय कर का निर्धारण करेगा।

उसके द्वारा ऐसे मूल्यांकन के आधार पर;

(घ) धारा 132 के तहत जब्त या धारा 132-ए के तहत अधिग्रहित परिसंपत्तियों से निम्नलिखित के अनुसार निपटा जाएगा -

धारा 132-बी के प्रावधान।

158 - BD.Undisclosed किसी अन्य व्यक्ति की आय।

जहां निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि कोई अज्ञात आय सम्मान के साथ व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है।

धारा 132 के तहत किसकी तलाशी ली गई या किसकी किताबें खाते या अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति की मांग की गई थी

धारा 132-ए के तहत, फिर, लेखा पुस्तकें, अन्य

जब्त किए गए या अधिग्रहित किए गए दस्तावेज या संपत्ति को सौंप दिया जाएगा। ऐसे अन्य पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को

व्यक्ति और वह निर्धारण अधिकारी धारा के तहत आगे बढ़ेंगे।

158 - बी. सी. ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध और इसके प्रावधान

अध्याय तदनुसार लागू होगा।

XXXXXXX

: . यह भी सामान्य बात है कि किसी यंत्र के प्रावधान की व्याख्या करते समय,

ई अदालतें किसी प्रावधान की व्याख्या इस तरह से करेंगी कि यह आरोप लगाने के प्रावधानों के लिए अर्थ रखता है और अदालतों द्वारा मशीनरी का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाता है।

माहिम पात्रम में आय कर अधिकारी v. विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

(पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ [(2007) 3 एस. सी. सी. 668] इस न्यायालय ने कहा है कि: (एस. सी. सी. पी. 680 , पैरा 25-26)

" 25. एक कर कानून निर्विवाद रूप से सख्ती से समझा जाना चाहिए। (जे. श्रीनिवास राव बनाम देखें। ए. पी. राज्य [(2006) 12 एस. सी. सी. 607]) हालांकि, यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि कर की गणना के लिए तंत्र प्रावधान या इसकी गणना के लिए प्रक्रिया निर्माण के सामान्य नियम द्वारा समझा गया। जबकि चार्जिंग सेक्शन द्वारा एक डीलर पर एक देयता लगाई गई है, यह अच्छी तरह से है

यह तय किया कि न्यायालय इस तरह के कानून का अर्थ लगाएगा

जिस तरह से मशीनरी को काम करने योग्य बनाया जा सके।

26. जे. श्रीनिवास राव [(2006) 12 एस. सी. सी. 607] में यह न्यायालय

गुरसाहई सहगल बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर ध्यान दिया। सीआईटी

[(1963) 48 आई. टी. आर. 1 (एस. सी.) और इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. कॉम.

सीमा शुल्क [(2006) 12 एस. सी. सी. 583]।

'17 . गुरसहाय सहगल [(1963) 48 आई. टी. आर. 1 (एस. सी.)] में प्रश्न

जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था

चार्जिंग प्रावधानों की तुलना में मशीनरी प्रावधानों का निर्माण। मोटर वाहन अधिनियम में संलग्न अनुसूची मशीनरी प्रावधान नहीं है। यह एक हिस्सा है

प्रभार का प्रावधान।

18. संलग्न अनुसूची को एक स्पष्ट अर्थ देकर

अधिनियम, मशीनरी प्रावधान नहीं बन जाता है

अव्यवहारिक। यह स्पष्ट इरादे को नहीं रोक पाया

विधायिका के पराजित होने से। यह दिया जा सकता है

उचित अर्थ "। 999

XXXXXXX

34. मशीनरी की व्याख्या करते समय यह अदालत का कर्तव्य है

अपने प्रकट उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए कर लगाने वाली कानून के प्रावधान। जहाँ कहीं भी दायित्व अधिरोपित करने का इरादा स्पष्ट है, न्यायालयों को तंत्र के प्रावधानों की सामान्य व्याख्या का समर्थन करने में

संकोच नहीं करना चाहिए ताकि आरोप विफल न हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मशीनरी के प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए जैसे कि

क्रानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी करें और उसे पराजित न करें (विह्टनी बनाम। आई. आर. सी. [1926 एसी 37 (एच. एल.)], सी. आई. टी. बनाम। महलिराम रामजीदास [(1939-40) 67 IA 239: (1940) 52 एलडब्ल्यू 234: (1940) 8 आई. टी. आर. 442], इंडियन यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड बनाम। कॉम. अतिरिक्त लाभ

कर [(1955) 27 आई. टी. आर. 20 (एस. सी.)] और गुरसाहई सहगल बनाम। सी. आई. टी. (1963)

23] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48 आई. टी. आर. 1 (एस. सी.); सी. डब्ल्यू. टी. बनाम। शरवन कुमार स्वरूप एंड संस [(1994) 6 एस. सी. सी. 623]; सी. आई. टी. बनाम। नेशनल ताज ट्रेडर्स [(1980) 1 एस. सी. सी. 370]; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड v. सीटीओ [(1981) 4 एससीसी 578]]। वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन में फ्रांसिस बेनिओन, 5 वीं संस्करण।, लेक्सिस नेक्सिस ने उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रक्रियात्मक प्रावधानों में विधायक द्वारा लगाए गए आरोप को वादियों और अन्य लोगों के सामान्य लाभ के लिए छोड़ दिया गया है, इसलिए यह माना जाता है कि यह लंबित के साथ-साथ भविष्य पर भी लागू होता है। कार्यवाही "।

10.7 गिरधारी लाल एंड संस (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक बार प्राथमिक इरादे का पता चल जाने के बाद और कानून के उद्देश्य और उद्देश्य का पता चल जाने के बाद, यह

कानून को उद्देश्यपूर्ण या कार्यात्मक बनाने का न्यायालय का कर्तव्य

व्याख्या। यह आगे देखा गया है कि किसी कानून की व्याख्या करने में अदालत का प्राथमिक और प्रमुख कार्य कानून के इरादे का पता लगाना है। विधायिका, वास्तविक या आरोपित। इरादे का पता लगाने के बाद, न्यायालय को कानून की इस तरह से व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके या आगे बढ़ाया जा सके। यह भी देखा गया है कि

विधायी आशय का निर्धारण वैधानिक निर्माण का एक बुनियादी नियम है और यह कि निर्माण के एक ऐसे नियम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो किसी विधान के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और हालांकि निर्माण, साधारण भाषा के अनुसार, सामान्य रूप से अपनाया जाना चाहिए, इस तरह के निर्माण को नहीं अपनाया जाना चाहिए जहां यह विसंगतियों, अन्याय या बेतुकेपन की ओर ले जाता है। कानून की व्याख्या पर, हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स (उपरोक्त) के मामले में पैरा 17 से 21 में इसे इस प्रकार देखा गया है इसके अंतर्गत:

" 17. यदि विकल्प दो व्याख्याओं के बीच है, तो संकीर्ण

जिसके प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगा

कानून, हमें ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कम हो जाए

निरर्थकता के लिए कानून, और इसके बजाय इस दृष्टिकोण के आधार पर साहसिक निर्माण को स्वीकार करना चाहिए कि संसद कानून बनाएगी

केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से।

(नोक्स वी. देखें। डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज [(1940) 3 ऑल ईआर 549 1940 एसी 1014: 109 एलजेकेबी 865: 163 एल. टी. 343 (एच. एल.)] जिसे पी. वी. में

संदर्भित किया गया है। एनएसडब्ल्यू के लिए भूमि मंत्री [(1954) 3 सभी ईआर 514: (1954) 1 डब्ल्यूएलआर 1410 (पीसी)]।) उक्त मामलों में बताए गए सिद्धांतों को इस न्यायालय ने मोहन कुमार मामले में दोहराया था।

सिंघानिया बनाम। भारत संघ [1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 594: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1]

आय कर अधिकारी v. विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

18. कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि संपूर्ण कानून को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके।

कानून।

19. न्यायालय को न केवल अर्थ लगाए जाने वाले खंडों पर बल्कि पूरे कानून पर अपना ध्यान केंद्रित करके विधायिका के इरादे का पता लगाना चाहिए; उसे खंड की तुलना कानून के अन्य हिस्सों और उस व्यवस्था से करनी चाहिए जिसमें खंड की व्याख्या की जानी है। (आर. एस. रघुनाथ बनाम देखें। कर्नाटक राज्य [(1992) 1 एससीसी 335: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 81]) इस तरह के निर्माण में किसी भी खंड के भीतर किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने का गुण है।

या एक ही कानून की दो अलग-अलग धाराओं या प्रावधानों के बीच। एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच टकराव से बचना अदालत का कर्तव्य है। (सुल्ताना बेगम बनाम देखें। प्रेम चंद जैन [(1997) 1 एस. सी. सी 373: ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1006]।

20. जब भी ऐसा करना संभव हो, यह उन प्रावधानों को समझने के लिए किया जाना चाहिए जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं ताकि वे सामंजस्य बना सकें। यह.

यह हल्के में नहीं लेना चाहिए कि संसद ने एक के साथ दिया था

हाथ जो वह दूसरे के साथ ले गया।

21. कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

उनके बीच सुलह। इस प्रकार एक निर्माण जो कम हो जाता है "बेकार लकड़ी" या "मृत पत्र" के प्रावधानों में से एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। सामंजस्य स्थापित करना विनाश करना नहीं है।

10.8 जहाँ तक संबंधित की ओर से प्रस्तुत करने की बात है

उत्तरदाता-निर्धारिती कि वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 153 सी में संशोधन के माध्यम से, यह निर्धारिती-व्यक्तियों को अपने दायरे में लाता है, जो

अब तक इसके दायरे में नहीं आए थे और इसलिए, यह निर्धारिती के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है और इसलिए, इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, संबंधित है, प्रस्तुत करना आकर्षक लगता है लेकिन अस्वीकार किए जाने योग्य है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यहां तक कि असंशोधित धारा 153 सी भी किसी अन्य व्यक्ति की आय के आकलन से संबंधित है। धारा 153 सी का उद्देश्य और उद्देश्य तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों को संबोधित करना है। यहां तक कि असंशोधित धारा 153 सी के अनुसार, अन्य व्यक्तियों (तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा) के खिलाफ कार्यवाही जब्त किए गए लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की जब्ती के आधार पर की गई थी, जो तलाशी लिए गए [2023] 2 एस. सी. आर. के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित या संबंधित थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्ति। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कि पेप्सिको इंडिया के मामले में हुआ था

अदालत। इसलिए, यदि संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया-आकलन करता है कि इस तथ्य के बावजूद कि आपत्तिजनक सामग्री है तलाशी लिए गए व्यक्ति के परिसर से लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या उनसे संबंधित संपत्तियों के रूप में पाए जाने पर भी उन्हें केवल इस आधार पर धारा 153 सी के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है कि संशोधन स्वीकार किए जाने से पहले तलाशी ली गई थी, उस मामले में, धारा 153 सी में संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य, जो "संबंधित या संबंधित" शब्दों के प्रतिस्थापन के रूप में है, निराश होगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कोई भी व्याख्या, जो अधिनियम/कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर सकती है, न्यायालय द्वारा टाल दी जाएगी। अगर

संबंधित प्रत्यर्थियों की ओर से प्रचार की गई व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, उस मामले में, किसी अन्य व्यक्ति (तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा) की आय के आकलन के लिए धारा 153 सी के उद्देश्य और उद्देश्य को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को अस्थिर माना जाता है और सवाल यह है कि, "क्या वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी में लाया गया संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत की गई खोजों पर लागू होगा, यानी संशोधन की तारीख? ", राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ जवाब दिया जाता है और तदनुसार जवाब दिया जाता है। इसलिए यह देखा और माना जाता है कि

वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी में लाया गया संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत 01.06.2015, यानी संशोधन की तारीख से पहले की गई खोजों पर लागू होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और तदनुसार रद्द कर दिया जाना चाहिए और दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित मूल्यांकन आदेशों को मुख्य रूप से उपरोक्त मुद्दे पर चुनौती दी गई थी, जिसे आयकर अधिकारी V.

विक्रम सुजीतकुमार भाटिया [एम. आर. शाह, जे.]

अब उपरोक्त के रूप में राजस्व के पक्ष में उत्तर दिया जाता है, हम संबंधित निर्धारिती के पक्ष में किसी भी अन्य आधार पर सी. आई. टी. (ए) के समक्ष मूल्यांकन आदेशों को चुनौती देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं जो उपलब्ध हो सकते हैं और यह देखा जाता है कि यदि कहा जाता है कि आज से चार सप्ताह के भीतर अपील की जाती है, तो उन पर कानून के अनुसार और उनके अपने गुण-दोष पर, किसी भी अन्य आधार पर विचार किया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान अपीलों की तदनुसार अनुमति दी जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन (अभिषेक प्रताप सिंह और तमन्ना, एलसीआरएएस द्वारा सहायता प्राप्त)